बिहार विधान परिषद्

190वां सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

वर्ग – 5

शुक्रवार, तिथि 9 अग्रहायण, 1940 (श.) / 30 नवम्बर, 2018 ई.

प्रश्नों की कुल संख्या – 12

1.	शिक्षा विभाग	-	-	12
			कुल योग –	12

परीक्षा का संचालन नहीं

29. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि मगध विश्वविद्यालय के सम्बद्ध डिग्री कॉलेजों के संबंधन के दीर्घीकरण एवं स्थायी मान्यता के लिए विश्वविद्यालय द्वारा मांगा गया प्रस्ताव विभाग में लम्बित है;

(ख) क्या यह सही है कि विभाग द्वारा अभी तक कॉलेजों के संबंधन प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किये जाने से विश्वविद्यालय ने बी.ए., बी.एस.सी. पार्ट-1 के परीक्षाफल पर रोक लगा दी है तथा बी.ए. पार्ट-2 एवं पार्ट-3 का परीक्षा-प्रपत्र लेने एवं परीक्षा लेने पर भी रोक लगा दी है, जिससे संबद्ध डिग्री कॉलेजों के छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार छात्रों के हित में संबंधन कॉलेजों का दीर्घीकरण एवं स्थायी मान्यता देने और लंबित परीक्षाफल घोषित कराने तथा खंड 'ख' में वर्णित वर्गों के छात्रों का परीक्षा-प्रपत्र स्वीकार करके उनकी परीक्षाएं संचालित कराने का विचार रखती है, यदि हां तो कबतक, नहीं तो क्यों?

प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन

30. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के 38 जिलों में कार्यरत जिला शिक्षा पदाधिकारियों, जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों एवं क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशकों को संवैधानिक, वित्तीय एवं विभागीय अधिनियमों, नियमों एंव परिपत्रों की जानकारी के लिए प्रशिक्षित किये बिना ही नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त शिक्षा सेवा के पदाधिकारी जो सेवा से पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण प्राप्त अनुभवी एवं दक्ष हैं, उनके नेतृत्व में प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन किया जा सकता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार ऐसी प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन कबतक करना चाहती है?

दिव्यांगों को लाभ कबतक

31. **श्री कृष्ण कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 में समावेशी शिक्षा के नाम से योजना बनाई थी, जिसके तहत राज्य के दिव्यांग विद्यार्थियों को शिक्षकों द्वारा घर जाकर पढ़ाने की बात कही गई थी, जिसके लिए 1177 शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत सभी सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों में एडमिशन सहित विभिन्न योजनाओं में 5 प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई थी, जिसमें स्कूलों में दिव्यांग शिक्षक व कर्मचारी प्रस्तावित थे, लेकिन इस नियम का पालन किसी भी स्कूल में नहीं हो रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण 5 साल गुजरने के बाद न विद्यार्थी प्रशिक्षित हुए और न ही योजना धरातल पर आई;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई और योजना का लाभ दिव्यांगों को दिलाना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

प्रस्वीकृति प्रदान कबतक

32. **मो. गुलाम रसूल** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा निबंधित 2459+1 मदरसों की जांच विभागीय संकल्प सं.-1090, दिनांक 24.11.1980 में निहित शर्त्तों के आलोक में जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कराई जाएगी तथा जांचोपरान्त निर्धारित शर्त्तों को पूरा करने वाले मदरसों को मदरसा बोर्ड द्वारा प्रस्वीकृति प्रदान की जायेगी;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड 'क' का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार यह बतलाएगी कि 2459+1 निबंधित मदरसों में से अबतक कितने मदरसों को मदरसा बोर्ड से प्रस्वीकृति प्रदान की गई है, कितने मदरसों की प्रस्वीकृति प्रक्रियाधीन है तथा इन्हें कबतक प्रस्वीकृति प्रदान की जायेगी?

रिक्त पदों पर नियोजन नहीं

33. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** एवं **श्री वीरेन्द्र नारायण यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के पावन उद्देश्य से राज्य में कुल 535 कस्तूरबा विद्यालय स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या यह सही है कि इन विद्यालयों में से 215 विद्यालय में वार्डन तथा 196 में नाइट गार्ड नहीं है, जिससे विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाएं असुरक्षित महसूस करती हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो अबतक सरकार द्वारा कस्तूरबा विद्यालय के वार्डन एवं नाइट गार्ड के रिक्त पदों पर नियोजन नहीं किये जाने का क्या औचित्य है?

बकाये का भुगतान

34. **श्री राधा चरण साह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि भोजपुर जिला के शिक्षकों को सातवें वेतन का एरियर अभी तक नहीं मिला है;

(ख) क्या यह सही है कि शिक्षकों को 1 जनवरी, 2015 से सैद्धान्तिक और 1 अप्रैल, 2017 से वास्तविक लाभ देना है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कब तक सातवें वेतन का एरियर और वास्तविक लाभ देना चाहती है?

वेतन पुनरीक्षण का लाभ कबतक

35. **प्रो. संजय कुमार सिंह** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के सभी सेवा संवर्गों के कर्मियों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिल रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों, मदरसा, संस्कृत तथा अल्पसंख्यक विद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मियों को भी सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ देय है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार खंड 'ख' में वर्णित महाविद्यालयों/विद्यालयों के शिक्षकों को सातवें वेतन पुनरीक्षण का लाभ प्रदान करना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

योजना का लाभ

36. **श्री ललन कुमार सर्राफ** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार हेतु मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के सभी छात्र-छात्राओं को पोशाक की राशि उपलब्ध करायी जानी है;

(ख) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत लाभान्वितों को लाभ पहुंचाने का कार्य काफी धीमा है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 2017-18 में कितने छात्र-छात्राओं का नामांकन हुआ और कितने को पोशाक योजना की राशि दी गई, कितनों को देना शेष है, अगर उक्त कार्य लंबित है तो क्या, शेष सभी को सरकार उक्त योजना का लाभ देना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

कर्मियों की सेवा बहाल

37. **प्रो. नवल किशोर यादव** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली ने दिनांक 22.10.2018 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा हटाये गये मुकेश कुमार एवं अन्य 9 कर्मियों की ओर से दायर अवमानना अर्जी पर सुनवाई के बाद उन 10 कर्मचारियों की सेवा बहाल करने का आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है;

(ख) क्या यह सही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 23 वर्षों तक काम करने वाले उन 10 कर्मियों को अक्टूबर, 2018 के अन्त तक सेवा में लेने का भी आदेश बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को दिया है, लेकिन अभी तक उनकी सेवा बहाल नहीं की जा सकी है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार न्याय-निर्णय के आलोक में उन 10 कर्मियों की सेवा बहाल कराने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों?

पाठ्यपुस्तक की व्यवस्था सुनिश्चित

38. **श्री केदार नाथ पाण्डेय** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि वर्ग 1 से 8 तक नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक सरकार उपलब्ध कराती है;

(ख) क्या यह सही है कि समाप्त हो रहे शैक्षणिक सत्र के बावजूद विद्यालयों में सभी छात्र-छात्राओं को बिना पाठ्यपुस्तक के ही परीक्षा एवं पढ़ाई के लिए उपस्थित होना पड़ता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार कबतक राज्य के सभी छात्र-छात्राओं को सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के पूर्व ही अनिवार्यत: उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहती है?

सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय कबतक

39. **श्री ललन कुमार सर्राफ** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि बिहार की सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय खोलने की सरकार की योजना है;

(ख) क्या यह सही है कि बिहार की कई पंचायतों में अभी तक उच्च विद्यालय नहीं खोले जा सके हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि कितनी पंचायतों में अब तक उच्च विद्यालय कार्यरत हैं और शेष कितनी पंचायतों में उच्च विद्यालय खोले जाने हैं, क्या सरकार सभी पंचायतों में उच्च विद्यालय खोलना चाहती है, यदि हां तो कबतक?

स्मार्ट क्लास चालू नहीं

40. **श्री रामचन्द्र पूर्वे** : क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

(क) क्या यह सही है कि राज्य के छात्रों को स्मार्ट के साथ टेक्नो-फ्रेंडली बनाने के लिए राज्य के दस सरकारी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सन् 2015 में स्मार्ट क्लास प्रारम्भ किया गया है;

(ख) क्या यह सही है कि स्मार्ट क्लास को सफल बनाने हेतु चयनित सभी विद्यालयों के विषयवार शिक्षकों को सम्पन्न प्रशिक्षण के साथ प्रत्येक विद्यालय को 50-50 हजार रुपये उपकरण आदि खरीदने के लिए दिये गये;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त व्यवस्था के बावजूद किसी भी चयनित विद्यालय में स्मार्ट क्लास नहीं चलने का क्या औचित्य है?

सुनील कुमार पंवार
सचिव
बिहार विधान परिषद्

पटना
दिनांक : 30 नवम्बर, 2018